

taken up by the Prime Minister with our Ambassador in Rangoon, who consulted the Burmese Government, and we proposed originally to put up a tablet in the place where these great leaders were imprisoned. Later on, we were informed by the Burmese Government that a tablet would only suggest to the people that these leaders died there, and that therefore, something else should be thought of. The present proposal is to have a class room-cum-lecture hall.

श्री नवाब सिंह चौहान : जैसा कि उत्तर में कहा गया है, यादगार की क्या शकल हो उस पर विचार हो रहा है। तो कितने दिन से विचार हो रहा है, और आपका फाइनल डिज़ीजन कब तक हो जायगा ?

SHRIMATI LAKSHMI MENON: We are in the final stages of negotiations.

श्री नवाब सिंह चौहान: मेरा प्रश्न यह है कि जब से बर्मा गवर्नमेंट ने आपको इजाजत दी तब से इस वक़्त तक इतनी देर होने का क्या कारण है ? क्या वजह है कि सरकार इस प्रश्न के ऊपर अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं ले सकी ?

SHRIMATI LAKSHMI MENON: Sir, the suggestion was made only by the end of 1954, and then, we had mooted the suggestion about this tablet and correspondence took some time and then it was suggested that we might put up a hospital or a little library, but the Burmese Government had already done so in the Mandalay jail and therefore, the final decision is to have a class room-cum-lecture hall. I think it is being finalised; even the size of the building is decided.

श्री नवाब सिंह चौहान : कब तक उम्मीद करें यह हो जायेगा ?

SHRIMATI LAKSHMI MENON: Very soon.

†English translation.

श्री देवकीनन्दन : मैं पूछना चाहूंगा कि मंत्री मद्दोदया जानती होंगी कि इस वर्ष हम लोग हिन्दुस्तान में लोकमान्य तिलक का शतसंवात्सरिक जन्म दिन मना रहे हैं। तो क्या यह हो सकेगा कि उससे पहले यह मेमोरियल, जिसकी योजना की जा रही है, तैयार हो जाये ?

SHRIMATI LAKSHMI MENON: I cannot give a definite answer to that question. Detailed estimates for this building are called for and I am sure it will be done very quickly.

SHRI MAHESHWAR NAIK: May I know whether reciprocal arrangements are available here in India also for the political leaders of other countries?

SHRIMATI LAKSHMI MENON: I do not think we have imprisoned foreign political leaders in our country.

SHRI DEOKINANDAN NARAYAN: May I know if the scheme would materialise before we observe this year the centenary of the birthday of Lokmanya Tilak?

SHRIMATI LAKSHMI MENON: I cannot give an answer to that.

श्री नवाब सिंह चौहान : उस पर कितना खर्च करने की व्यवस्था है, क्या उस पर कुछ विचार किया गया है ?

SHRIMATI LAKSHMI MENON: About 50 to 80 thousand rupees.

डीजल कार बनाने की योजना

*१०२. **श्री नवाब सिंह चौहान :** वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को देश में डीजल-कारें बनाने की किन्हीं ऐसी योजनाओं की सूचना है जिनके निकट भविष्य में कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

t [SCHEME FOR PRODUCTION OF DIESEL CARS

*102. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister for COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state whether Government are aware of any schemes with regard to the production in the country of cars run by diesel oil which are likely to be implemented in the near future?]

उद्योग मंत्री (श्री नित्यानन्द कानूनगो):

जी, नहीं।

†[THE MINISTER FOR INDUSTRIES (SHRI N. KANUNGO): No, Sir.]

श्री नवाब सिंह चौहान : क्या मेरे प्रश्न पूछने के बाद सरकार ने इस बात की जांच की थी कि कोई निजी तौर से इस प्रकार के डीजल इंजन की गाड़ियां बनाने का प्रयत्न कर रहा है ?

श्री नित्यानन्द कानूनगो : जांच की गई है, और ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

डा० रघुबीर सिंह : क्या टाटा कम्पनी की मदद से ऐसी गाड़ियां बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया ?

श्री नित्यानन्द कानूनगो : जी, नहीं।

SHRI BARKATULLAH KHAN: Is it a fact that diesel cars are cheaper to run and easy to maintain?

SHRI N. KANUNGO: It is a matter of opinion.

श्री नवाब सिंह चौहान : क्या कभी सरकार ने इस प्रश्न के ऊपर विचार किया है कि डीजल कार बनाई जाय ?

श्री नित्यानन्द कानूनगो : नहीं, इसका विचार नहीं किया गया।

श्री नवाब सिंह चौहान : क्या कारण है कि जब पेट्रोल कार और लारियों की

जगह पर डीजल इंजन की गाड़ियां मंगाई जा रही हैं, तो क्यों इस बात को नहीं समझा जा रहा है कि पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले डीजल की गाड़ियां बनाई जाय ?

श्री नित्यानन्द कानूनगो : पहले वे गाड़ियां तो पूरी तौर से बनाई जाय, फिर डीजल की गाड़ियां बनाई जायेंगी।

डा० रघुबीर सिंह : क्या डीजल के ट्रक्स नहीं बन रहे हैं ?

श्री नित्यानन्द कानूनगो : एसेम्बल कर रहे हैं, बनाने की कोशिश हो रही है।

डा० रघुबीर सिंह : जब ट्रक्स और कार बनाने की कोशिश हो रही है तो मिनिस्टर साहब कैसे कहते हैं कि इस पर विचार नहीं हो रहा है ?

श्री नित्यानन्द कानूनगो : ट्रक पूरी तरह नहीं बनाई जाती है, उसके पार्ट्स एसेम्बल किये जाते हैं।

डा० रघुबीर सिंह : क्या कार ट्रक की श्रेणी में नहीं आती ?

SHRI N. KANUNGO: No, Sir.

DR. R. P. DUBE: Is it not a fact that the Bihar Government has placed an order with the Tatas to make Mercedes-Benz trucks for road transport?

SHRI N. KANUNGO: Not Bihar Government. They have been doing it for anybody who wants to buy.

DR. RAGHUBIR SINH: In that case I do not understand why he says that these cars are not being built in India.

SHRI N. KANUNGO: It is not car: they are making trucks.

DR. RAGHUBIR SINH: I do not think 'car' means only a car which is used for carrying passengers.

SHRI N. KANUNGO: There is a difference, Sir.

†English translation.

DR. RAGHUBIR SINH: Are these buses not included in cars?

SHRI N. KANUNGO: No. No, Sir.

नई दिल्ली की लघु उद्योग-सहायता संस्था

*१०३. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में नई दिल्ली में जो लघु उद्योग-सहायता-संस्था स्थापित की गई है, उसमें देश तथा विदेश के कितने तथा किस योग्यता के विशेषज्ञ रखे गये हैं ; और

(ख) इस पर प्रति वर्ष कितना धन व्यय होगा ?

f [SMALL INDUSTRIES SERVICE INSTITUTE, NEW DELHI

*103. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister for COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number and qualifications of the Indian and foreign experts employed at the Small Industries Service Institute set up recently at New Delhi: and

(b) the expenditure to be incurred on it every year?]

उद्योग मंत्री (श्री नित्यानन्द कानूनगो) : (क) नई दिल्ली की लघु उद्योग-सहायता-संस्था में कोई भी विदेशी विशेषज्ञ नहीं रखा गया है। इस में रखे गये टेक्नीकल अफसरों (गजेटेड) की योग्यताओं और अनुभव विषयक एक विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत किया जाता है। [देखिये परिशिष्ट १३, अनुपत्र संख्या १६]

(ख) १९५५-५६ में नयी दिल्ली की संस्था पर ३.५ लाख (लगभग) रुपये व्यय हुये हैं। चालू वर्ष में यह व्यय और बढ़ेगा।

THE MINISTER FOR INDUSTRIES (SHRI N. KANUNGO) : (a) No foreign experts are employed at the Small Industries Service Institute, New Delhi. A brief statement of qualifications and experience of Technical Officers (gazetted) employed at the Institute, is laid on the Table of the House. [See Appendix XIII, Annexure No. 16.]

(b) During 1955-56 an expenditure of Rs. 3.5 lakhs (approximately) was incurred on the New Delhi Institute. The expenditure will however, increase during the current year.

श्री नवाब सिंह चौहान : इसमें कितने शिक्षार्थियों को प्रतिवर्ष शिक्षा दी जाती है और शिक्षा पाने के बाद कितने लोगों को सरकारी और गैर सरकारी जगहों पर खपाया और जगह दी जाती है ?

श्री नित्यानन्द कानूनगो : शिक्षार्थियों का इन्तजाम यहां नहीं है। यह तो एक सर्विसेज इन्स्टीट्यूट है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके जो प्रॉब्लम हैं, उनको हल करने की यहां पर कोशिश की जाती है।

श्री नवाब सिंह चौहान : कितने ऐसे लोगों को यहां पर परामर्श दिया गया है ?

श्री नित्यानन्द कानूनगो : मुझे जहां तक मालूम है, आखिरी क्वार्टर में, करीब २२०० सी चिट्ठिया मिलीं और इन्टरव्यू किये गये।

PROF. G. RANGA: Is it proposed to make this service a permanent one, and if so, how soon do the Government propose to make it permanent?

SHRI N. KANUNGO: It is there. I do not see why it should not be permanent but experience has got to be gained before it can be expanded or made permanent.

PROF. G. RANGA: In view of the fact that this service has been brought into existence as a result of the recommendations made by an Expert Committee, do the Government want